

Daily Current Affairs

Date : 14 February, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डवलपमेंट कॉन्क्लेव में राजस्थान
2.	राजस्थान में नाबार्ड द्वारा चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्र
3.	राजस्थान के निर्यात सेक्टर से संबंधित नवीनतम आँकड़े
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2026 2. रियान पराग - राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान 3. राज्य का प्रथम 'नेफेड बाजार' 4. मोना जाट - शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप के लिए चयन 5. वास्तुकार प्रमोद जैन : ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवॉर्ड (AISA)
5.	बैसिलिस सबटिलिस
6.	पंक ज्वालामुखी (Mud Volcanoes)
7.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: आधार वर्ष 2024
8.	मूल प्रस्ताव (Substantive Motion)
9.	संयुक्त समुद्री बल (CMF)
10.	बांग्लादेश

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डवलपमेंट कॉन्क्लेव में राजस्थान



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नई दिल्ली में नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डवलपमेंट कॉन्क्लेव - 2026 का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार द्वारा अपनाई गई अफोर्डेबल हाउसिंग, गुणवत्ता सुधार एवं स्किल विकास योजनाओं की सराहना की गई।



मुख्य बिन्दु:

- इस कॉन्क्लेव में राजस्थान आवासन मंडल आयुक्त द्वारा आवास निर्माण में गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी और श्रमिक प्रशिक्षण को प्राथमिकता बताते हुए बोर्ड की प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जबकि सतत विकास सत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने ट्रांजिट आधारित शहरी विकास को आने वाले समय का निर्णायक मॉडल बताया।

--2--

ट्रांजिट-ओरिएंटेड डवलपमेंट (TOD) नीति :

- राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा 'ट्रांजिट-ओरिएंटेड डवलपमेंट (TOD) नीति' का अनुमोदन किया गया है। प्रारम्भिक चरण में 'नगरीय विकास एवं आवासन विभाग' द्वारा जयपुर में इस नीति के प्रावधान लागू किए जाएंगे।
- राज्य के प्रमुख शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण, कंजेशन और अव्यवस्थित विस्तार को देखते हुए इस नीति को लागू किया जा रहा है।
- TOD एक आधुनिक शहरी विकास मॉडल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास कॉम्पैक्ट, मिश्रित-उपयोग एवं उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों का विकास करना है। यह पैदल एवं गैर-मोटर चालित परिवहन (NMT) को प्रोत्साहित कर शहरों को अधिक सुगम, पर्यावरण-अनुकूल और रहने योग्य बनाता है।
- यह नीति न केवल सुगम एवं स्मार्ट गतिशीलता को बढ़ावा देगी बल्कि शहरों की आर्थिक क्षमता और रहने की गुणवत्ता को भी नई दिशा प्रदान करेगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डवलपमेंट कॉन्क्लेव - 2026

- आयोजन अवधि : 13 और 14 फरवरी, 2026
- आयोजन स्थल : यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली।
- आयोजक : नेशनल रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) द्वारा केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तत्वावधान में।

राजस्थान में नाबार्ड द्वारा चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा जयपुर में 'नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर-2026-27' का विमोचन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान के लिए नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर में वित्त वर्ष 2026-27 हेतु ₹4.88 लाख करोड़ की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया है।
- इस आकलन में ₹2.24 लाख करोड़ कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों तथा ₹2.27 लाख करोड़ MSMEs क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं, जो कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में संतुलित विकास रणनीति को दर्शाता है।
- राजस्थान में नाबार्ड (NABARD) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन कर रहा है; जैसे -

--4--

- **जनजातीय विकास (WADI) :** उदयपुर, बाँसवाड़ा और बारां सहित 15 जिलों में 51,000 से अधिक जनजातीय परिवारों को फलों के बागों (आम, अमरूद) और बकरी पालन जैसे आजीविका साधनों से जोड़ा गया है।
- **किसान उत्पादक संगठन (FPO) :** छोटे किसानों को संगठित करने के लिए नए FPO बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके।
- **सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण :** प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण और अनाज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण का कार्य।
- **जल एवं मृदा संरक्षण :** जलसंभर (Watershed) परियोजनाओं के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में जल संचयन और मिट्टी की उर्वरता सुधारने पर कार्य किया जा रहा है।
- **सूक्ष्म वित्त और कौशल विकास :** स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बैंक से लिंक करना और ग्रामीण युवाओं व कारीगरों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

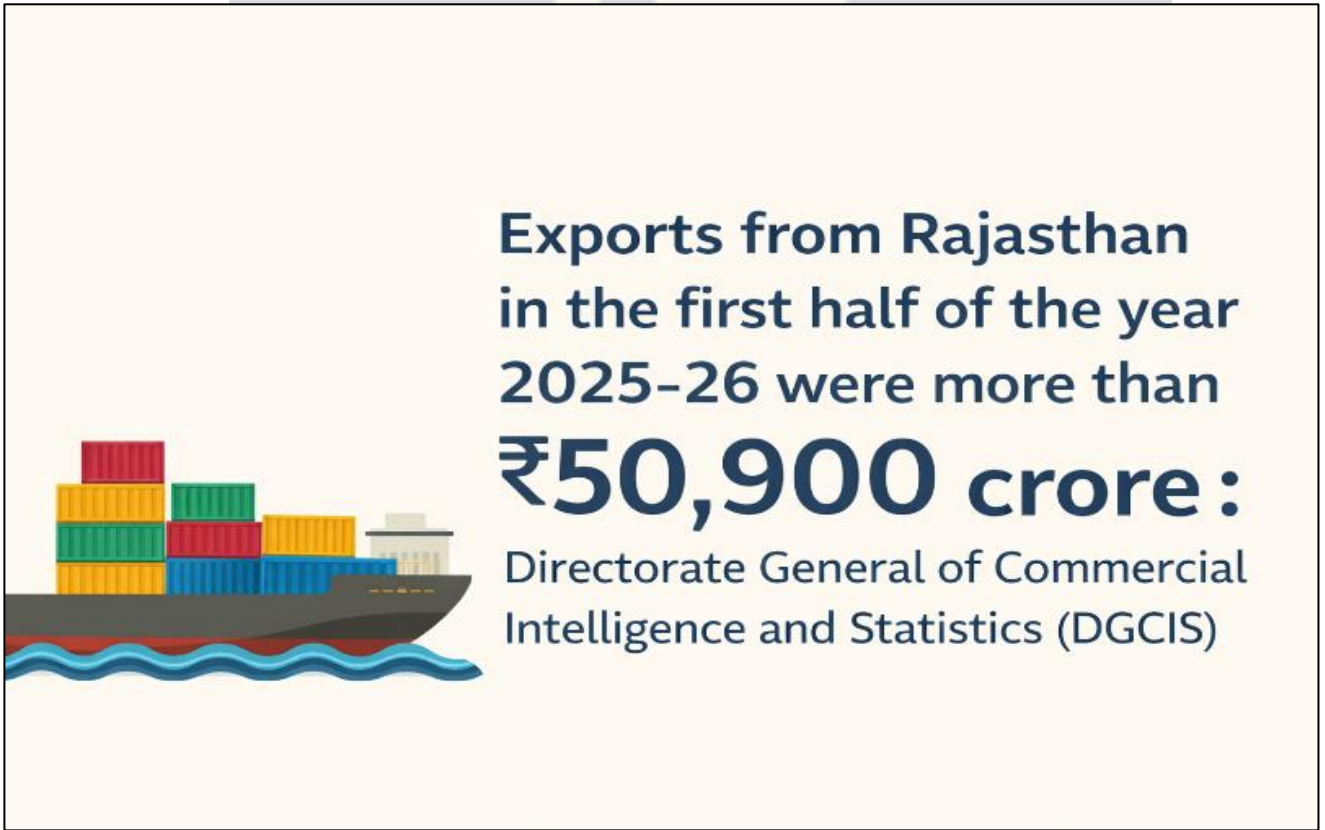
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट (NABARD)

- **स्थापना :** 12 जुलाई, 1982 को नाबार्ड अधिनियम, 1981 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में।
- **समिति :** इसकी स्थापना बी. शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी।
- **योजना :** छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान स्थापित।
- **उद्देश्य :** कृषि, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी के रूप में कार्य।
- **संबंध मंत्रालय :** वित्त मंत्रालय (भारत सरकार)
- **मुख्यालय :** मुंबई, महाराष्ट्र।
- **अध्यक्ष :** शाजी के.वी.।

राजस्थान के निर्यात सेक्टर से संबंधित नवीनतम आँकड़े

चर्चा में क्यों?

- वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) द्वारा हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में राजस्थान से ₹50,900 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ है।



मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान से वर्ष 2024-25 में कुल ₹97,171 करोड़ से अधिक का निर्यात हुआ जो वर्ष 2023-24 के कुल निर्यात (₹83,704 करोड़) की तुलना में ₹13,467 करोड़ अधिक है।
- राजस्थान की पाँच प्रमुख निर्यातक वस्तुएँ : इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रत्न एवं आभूषण, धातु, वस्त्र तथा हस्तशिल्प। इन सभी वस्तुओं का राज्य के निर्यात में 67 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

Daily Current Affairs

Date : 14 February, 2026



- राजस्थान से कपड़ा निर्यात वर्ष 2024-25 में ₹9700 करोड़ से अधिक रहा, जबकि वर्ष 2023-24 में यह आँकड़ा ₹8819 करोड़ था। वहीं, रत्न एवं आभूषण सेक्टर का वर्ष 2024-25 में ₹17,567 करोड़ से अधिक का निर्यात था। अभियांत्रिकी सेक्टर से वर्ष 2024-25 में ₹19,849 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया जबकि वर्ष 2023-24 में इस सेक्टर से ₹16592 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। (आर्थिक समीक्षा 2025-26 के आँकड़ों के अनुसार)
- धातु सेक्टर में लोह एवं अलोह श्रेणी से वर्ष 2024-25 में ₹1024 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया गया। वर्ष 2023-24 में इस सेक्टर की दोनों श्रेणियों से कुल ₹9857 करोड़ रुपये का ही निर्यात हुआ।
- हस्तशिल्प वस्तुओं का वर्ष 2024-25 में ₹8444 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ। यह निर्यात आँकड़ा वर्ष 2023-24 में ₹7986 करोड़ रुपये था।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान सरकार की निर्यात प्रोत्साहन संबंधी प्रमुख नीतियाँ:

- राजस्थान इंडस्ट्रियल डवलपमेंट पॉलिसी, 2019
- राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, 2022
- राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2024
- राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी - 2025
- RIICO डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी - 2025
- राजस्थान टैक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी - 2025
- राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS), 2024

--7--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन-2026</p> <ul style="list-style-type: none">16 और 17 फरवरी, 2026 को जयपुर में राष्ट्रीय संस्थानिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन (NSIL) 2026 का आयोजन किया जाएगा।यह शिखर सम्मेलन उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताओं के लिए एक प्रमुख मंच है, जिसका उद्देश्य 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य के अनुरूप भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के प्रभाव और संस्थानिक विकास पर चर्चा करना है।स्थान : राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर।
2.	<p>रियान पराग - राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान</p> <ul style="list-style-type: none">इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रियान पराग को आगामी IPL 2026 सीजन के लिए अपना नया कप्तान नियुक्त किया है।रियान पराग, संजू सैमसन का स्थान लेंगे जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने खरीदा है।
3.	<p>राज्य का प्रथम 'नेफेड बाजार'</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने नेहरू सहकार भवन, जयपुर में नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) द्वारा शुरू किये गए रिटेल आउटलेट 'नेफेड बाजार' का उद्घाटन किया।'किसान से किचन तक' की संकल्पना पर आधारित इस 'नेफेड बाजार' के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे।

4.	<p>मोना जाट - शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप के लिए चयन</p> <ul style="list-style-type: none">■ जयपुर की मोना जाट का चयन द्वितीय शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप, 2026 के लिए भारतीय महिला टीम में हुआ।■ इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 3 फरवरी, 2026 तक हुआ।■ स्थान : जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली।■ नोट : भारतीय महिला टीम ने इस विश्व कप के फाइनल में नेपाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
5.	<p>वास्तुकार प्रमोद जैन : ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवॉर्ड (AISA)</p> <ul style="list-style-type: none">■ वास्तुकार प्रमोद जैन को उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर (MIC), जोधपुर के लिए प्रतिष्ठित 12वाँ ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चरल अवॉर्ड (AISA)-2025 प्रदान किया गया।■ उन्हें यह पुरस्कार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के JECC सीतापुरा में आयोजित 'इंडिया स्टोन मार्ट' के दौरान प्रदान किया।■ जोधपुर स्थित MIC भवन स्थानीय सूरसागर सैंडस्टोन (बलुआ पत्थर) से निर्मित है, जो जोधपुर की पारंपरिक विरासत और आधुनिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट मिश्रण है।

SERVICES

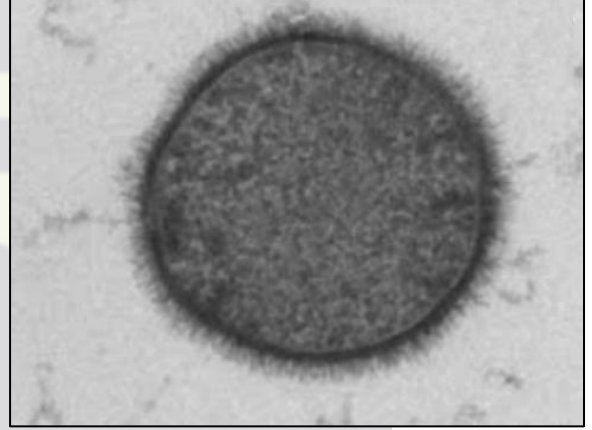


बैसिलस सबटिलिस



चर्चा में क्यों?

- केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने 'बैसिलस सबटिलिस' को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है।



मुख्य बिन्दु:

बैसिलस सबटिलिस

- यह एक प्रकार का प्रोबायोटिक (अच्छा बैक्टीरिया) है, जो पर्यावरण में व्यापक रूप से पाया जाता है।
- यह मनुष्यों की आँत में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है और किण्वित खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है।
- **औद्योगिक दृष्टि से महत्व:** यह एंजाइम (जैसे एमाइलेज, प्रोटीज), एंटीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
- इसका कृषि और पशु आहार में प्रोबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है।
- इसका सामान्य रूप से सुरक्षित के रूप में मान्यता (GRAS) दर्जा, इसे खाद्य और औषधि क्षेत्रों में उपयोगी बनाता है।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

पंक ज्वालामुखी (Mud Volcanoes)

चर्चा में क्यों?

- अंडमान द्वीप समूह के दिगलीपुर में एक दुर्लभ पंक ज्वालामुखी उद्गार की घटना दर्ज की गई है।



मुख्य बिन्दु:

- अंडमान द्वीप समूह कई विवर्तनिक प्लेटों की अभिसरण सीमाओं के पास स्थित है। इसलिए यह भूकंप और ज्वालामुखी प्रवण क्षेत्र है।

पंक ज्वालामुखी

- ये ऐसी भूगर्भीय संरचनाएँ हैं जो भूमिगत दबाव के कारण पंक, जल और गैसों (मुख्य रूप से मीथेन) का मिश्रण उत्सर्जित करती हैं।
- इसमें मैग्मा नहीं निकलता।
- **उत्पत्ति:** ये ज्वालामुखी उद्गार विवर्तनिक गतिविधि, तलछट संपीडन और हाइड्रोकार्बन युक्त क्षेत्रों से जुड़े होते हैं।
- **विशेषताएँ:** इनका पंक ठंडा होता है या शायद स्थलीय तापमान से थोड़ा ही गर्म होता है।
- **महत्व:** ये भूमिगत गैस भंडार और सक्रिय भूगर्भीय प्रक्रियाओं के संकेतक होते हैं।

आर्थिक घटनाक्रम

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: आधार वर्ष 2024

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। मंत्रालय द्वारा इस नई श्रृंखला के तहत पहला डेटा जारी किया गया।



मुख्य बिन्दु:

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- परिचय:** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) उन वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है, जिन्हें परिवार अपने दैनिक उपभोग के लिए खरीदते हैं।
- अन्य नाम:** इसे 'खुदरा मुद्रास्फीति' का संकेतक भी कहा जाता है।
- जारीकर्ता:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।
- बास्केट:** इसमें भोजन, कपड़े, आवास, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कई श्रेणियाँ शामिल होती हैं।
- महत्व:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अपनी मौद्रिक नीति तय करने के लिए मुख्य रूप से CPI (Combined) को ही बेंचमार्क मानता है।

--:12:--

CPI 2024 श्रृंखला में क्या-क्या बदला?

- **कवरेज विस्तार:** अब डेटा 1,465 ग्रामीण बाजारों और 1,395 शहरी बाजारों से एकत्र किया जा रहा है। (पहले से काफी अधिक)
- **वस्तुओं की संख्या में वृद्धि:** उपभोग टोकरी का विस्तार किया गया है। कुल वस्तुओं की संख्या 299 से बढ़कर 358 हो गई है।
- **वस्तुएँ (Goods):** 259 से बढ़ाकर 308।
- **सेवाएँ (Services):** 40 से बढ़ाकर 50।
- **भार में बदलाव:** परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 2023-24) के आधार पर वस्तुओं के भार को पुनः निर्धारित किया गया है:
- **खाद्य और पेय पदार्थ:** इनका भार 45.86% से घटकर 36.75% रह गया है। यह दर्शाता है कि भारतीय परिवारों का खर्च अब भोजन की तुलना में अन्य सेवाओं पर बढ़ रहा है।
- **आवास:** इसमें अब पानी, बिजली और गैस जैसे उपयोगिताओं को शामिल किया गया है, जिससे इसका भार 10.07% से बढ़कर 17.67% हो गया है।
- **आधुनिक वस्तुओं का समावेश:** डिजिटल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए OTT सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन मीडिया सेवाएँ, पेन ड्राइव, एक्सरसाइज उपकरण और बेबीसिटर सेवाओं जैसे आधुनिक खर्चों को जोड़ा गया है।
- **नई श्रेणियाँ:** सूचकांक को अब 6 के बजाय 12 डिवीजनों में विभाजित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के COICOP 2018 (Classification of Individual Consumption According to Purpose) ढाँचे के अनुरूप हैं।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

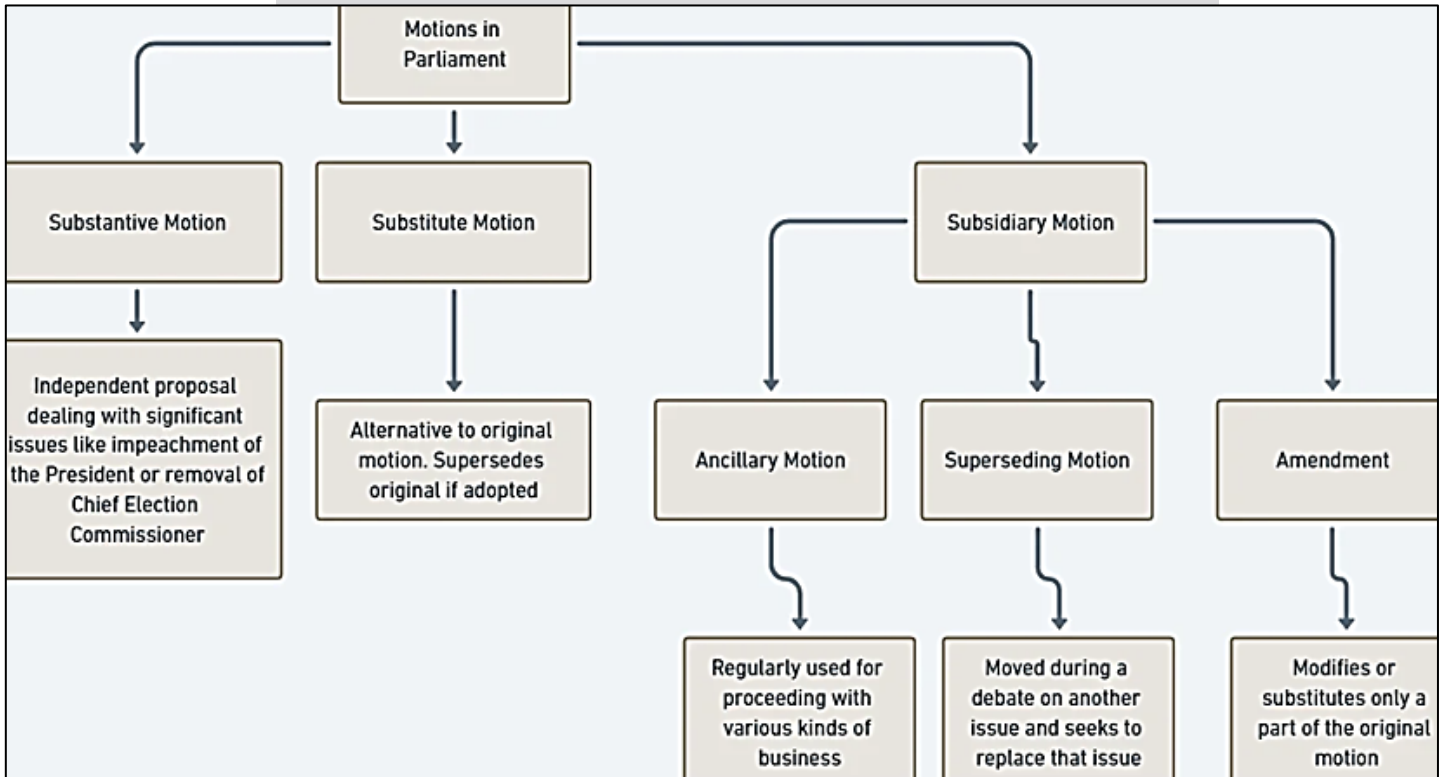
मूल प्रस्ताव (Substantive Motion)

चर्चा में क्यों?

- एक सांसद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध एक मूल प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है।

मुख्य बिन्दु:

- प्रस्ताव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई सदस्य सदन से किसी विषय पर निर्णय या राय माँगता है।



मूल प्रस्ताव (Substantive Motion)

- यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव है, जिसे किसी विशेष विषय पर चर्चा और निर्णय के लिए पेश किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 14 February, 2026



- उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के आचरण पर चर्चा केवल उचित शब्दों में तैयार किए गए मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव, या अविश्वास प्रस्ताव मूल प्रस्तावों के उदाहरण हैं।
- किसी सांसद के विरुद्ध मूल प्रस्ताव के परिणामस्वरूप निंदा (सदस्यता समाप्त किए बिना आचरण की अस्वीकृति), निलंबन, निष्कासन हो सकता है।

अन्य प्रमुख प्रस्ताव

- **सहायक प्रस्ताव (Subsidiary Motion):** यह मूल प्रस्ताव पर निर्भर होता है और चर्चा को नियंत्रित करने के लिए लाया जाता है। उदाहरण: संशोधन या स्थगन प्रस्ताव।
- **स्थानापन्न प्रस्ताव (Substitute Motion):** यह मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया जाता है, ताकि किसी नीति या स्थिति पर नए सिरे से विचार किया जा सके।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:15:-

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

संयुक्त समुद्री बल (CMF)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स-154 (CTF-154) की कमान संभाली है।



मुख्य बिन्दु:

- CTF-154, संयुक्त समुद्री बल (Combined Maritime Forces: CMF) के तहत एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण टास्क फोर्स है।

संयुक्त समुद्री बल (CMF)

- यह समुद्री क्षेत्र में सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय साझेदारी है। इसे "इच्छुक देशों का गठबंधन" कहा जाता है।
- यह अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करता है।
- **सदस्य:** भारत सहित 47 राष्ट्र। इसमें योगदान स्वैच्छिक और लचीला है।
- **दायित्व:** अवैध गैर-राज्य तत्त्वों का मुकाबला करना; समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और वैश्विक व्यापार की मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करना।

--:16:--

बांग्लादेश

चर्चा में क्यों?

- तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) ने आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिससे अवामी लीग के लगभग दो दशकों के राजनीतिक वर्चस्व का अंत हो गया है।

मुख्य बिन्दु:

- बांग्लादेश में एक सदनीय विधायिका - जातीय संसद (राष्ट्रीय संसद) के सदस्यों को चुनने के लिए संसदीय चुनाव होते हैं।

संसद की संरचना:

- कुल 350 सीटें
- फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के माध्यम से 300 सीधे निर्वाचित होंगे
- महिलाओं के लिए 50 आरक्षित सीटें (आनुपातिक रूप से आवंटित)

विजेता (2026 चुनाव):

- तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ।
- लगभग 218 सीटें जीतकर उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया।
- जमात-ए-इस्लामी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी।

भारत से रिश्ता कितना बदलेगा?



- भारत विरोधी माहौल के बीच नए रिश्तों पर जोर
- द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से तय करने का मौका

- लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता के बाद शांति
- सीमा और सुरक्षा सहयोग पर बेहतरी की उम्मीद



बांग्लादेश के बारे में :

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है जो पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध के बाद 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।

पड़ोसी राष्ट्र:

- भारत (पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) - तीन तरफ से
- म्यांमार (बर्मा) - दक्षिणपूर्व
- दक्षिण में बंगाल की खाड़ी

भौगोलिक विशेषताएँ:



Daily Current Affairs

Date : 14 February, 2026



- **डेल्टा क्षेत्र:** गंगा (पद्मा), ब्रह्मपुत्र (जमुना) और मेघना नदियों के विशाल डेल्टा में स्थित- जो दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टाओं में से एक है।
- **नीचा भूभाग:** अधिकांश भूमि समुद्र तल से 30 फीट से कम ऊँचाई पर स्थित है, जिससे यह अत्यधिक बाढ़-प्रवण क्षेत्र बन जाता है।
- **सुंदरबन:** दक्षिण-पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन।
- **चटगाँव हिल ट्रेक्ट्स:** दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी क्षेत्र।
- **अत्यधिक नदी-प्रधान प्रणाली:** नदियाँ अक्सर भू-दृश्य को नया आकार देती हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी का जमाव और विनाशकारी बाढ़ दोनों होती हैं।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:19:-